

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. बंसदरुब्बान्या) : (क) राज्य सरकार तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व के अधीन बरिष्ठ पदों के अधिक से अधिक 33 प्रतिशत पद (1) राजस्थान प्रशासनिक सेवा के स्थाई सदस्यों में से तथा (2) उन अधिकारियों में से, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्य तो नहीं हैं परन्तु राज्य सरकार के अधीन स्थायी रूप में राजपत्रित पदों पर हैं, भर्ती के लिये होते हैं।

(ख) तथा (ग) : भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग के पदोन्नति कोटे में 46 पदों पर, जो कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सदस्यों के लिये नियत हैं, 34 अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्त हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा में एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार से प्राप्त हुई सिफारिश विचाराधीन है। शेष 11 रिक्तियों पर नियुक्ति पर इस संबंध में राज्य सरकार से सिफारिश प्राप्त होते ही भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विचार किया जायगा।

(घ) तथा (ङ). प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ कामिक प्रशासन पर अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की थी कि श्रेणी-I में पदोन्नति द्वारा भरा जाने वाला रिक्तियों का कोटा उस अवस्था में अधिक से अधिक 40 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाए जहां वर्तमान कोटे की प्रतिशतता 40 प्रतिशत से कम हो। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के पदोन्नति कोटे में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार किया गया था और पदोन्नति कोटे को 25 प्रतिशत से बढ़ा कर 33 प्रतिशत करने का निर्णय किया गया था। तदनुसार, राज्य सरकारों तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० (भर्ती) नियमों को 5 जुलाई, 1977 से संशोधित कर दिया गया था।

Registered Crimes

2642. SHRI G. NARSIMHA REDDY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of crimes registered in the last two years and the

total number of cases where convicts were punished; and

(b) whether Government propose to give some more powers to police to detect cases or there are any other proposals to check the present trend of increase in criminal cases?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) and (b). The requisite information is being collected and on receipt of the same a statement will be laid on the Table of the House.

Withdrawal of Criminal Cases

2643. SHRI G. M. BANATWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many criminal proceedings instituted by the Government have been withdrawn during the period after January, 1980 on the grounds of lack of evidence, or public policy or their being politically motivated or being frivolous in nature;

(b) the names of persons against whom such proceedings had been instituted and alleged offences; and

(c) whether Government propose to take action against officials and those responsible for institution of such criminal proceedings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. VENKATASUBBAIAH): (a) and (b). The required information is given in the attached statement.

(c) No such proposal is now under the consideration of the Government.